VESTASPACE GEARS 35 SATELLITES FOR 5G

Vestaspace Technology will launch 35 satellites to build 5G speed network connections and IoT functionalities for industries.

The beta version of satellite constellations will be ready pan-India in September and fully-operational version early next year into Low-Earth-Orbit or Geosynchronous Equatorial Orbit.

The company plans to replace traditional fibre networks with all the satellite constellations and to provide high-speed 5G network connections PAN India with its unmanned Software Data processing.

Arun Kumar Sureban, Founder & CEO, Vestaspace Technology said, "To solve the complex system and to provide 5G internet network solutions to the Urban, Rural and unserved regions, we have positioned 8 Ground Stations and 31,000 data receptors all over India. This is made possible with the help of accurate positioning and telemetry related activities."

The Pune-based startup has secured USD 10 million funding from an American investment and advisory firm Next Capital LLC, and has been working with ISRO, NASA and other leading space agencies on various strategic projects.

5जी के लिए 35 सैटेलाइटों की तैयारी कर रहा है विस्तास्पेस

विस्तास्पेस टेक्नोलॉजी, उद्योगों के लिए आईओटी गतिविधियों व 5जी स्पीड नेटवर्क कनेक्शन के निर्माण के लिए 35 सैटेलाइट लॉन्च करेगा।

सैटेलाइट नक्षत्रों का बीटा संस्करण, पूरे भारत के लिए सितंबर और लो–अर्थ–ऑर्बिट या जियोसिंक्रोनस इक्वेटोरियल कक्षा में अगले साल की शुरूआत में पूरी तरह से संचालन संस्करण आ जायेगा। कंपनी की योजना सभी सैटेलाइट नक्षरों के साथ पारंपरिक नेटवर्क को बदलना है और अपने मानव रहित सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग के साथ पूरे भारत को उच्च गति 5जी नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करना है।

विस्तास्पेस टेक्नोलॉजी के संस्थापक व सीईओ अरूण कुमार सुबर्न ने बताया कि 'जटिल प्रणाली को हल करने के लिए और शहरी, ग्रामीण व अनछुए क्षेत्रों में 5जी इंटरनेट नेटवर्क समाधान प्रदान करने के लिए, हमने पूरे भारत में 8 ग्राउंड स्टेशन और 31000 डेटा रिसेप्टर्स तैनात किये हैं।इसे सटीक स्थिति और टेलीमेट्री से संबधित गतिविधियों की मदद से संभव बनाया गया।'

पुणे स्थित स्टार्टअप ने एक अमेरिकी निवेश और सलाहकार कंपनी नेक्स्ट कैपिटल एलएलसी से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड हासिल किया है, और इसरो, नासा और अन्य प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ विभिन्न रणनीतिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

BOOKINGS OPEN

The 29th
SCAT INDIA 2020
29-31 OCTOBER 2020
Bombay Exhibition Centre, Goregaon (W), Mumbai

SCAT2020
SAT & CABLE TV INDIA ▪ MUMBAI
29 - 31 October 2020

Organised By:
NÜRNBERG MESSE

BOMBAY EXHIBITION CENTRE GOREGAON (E) - MUMBAI - INDIA

Tel.: +91-22-62165303 Mob.: +91-7021850198 / 9945826427 Email: varun.gaba@nm-india.com / scat.sales@nm-india.com

TRAI'S REGULATES INTERCONNECTION AGREEMENTS

TRAI dictated all the broadcasters and distributors of television channels to comply with all the provisions of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Register of Interconnection Agreements and all such other matters Regulations, 2019. And to submit all the documents/ reports as per Register Regulation 2019 on the Broadcasting & Cable Services integrated (BlPS) portal, developed by TRAI for the purpose. The Register of Interconnect Module is accessible on the link: https://bips.trai.gov.in.

However, it has been noted that many of the service providers are not complying with all the provisions of the Register Regulation 2019 and they have not uploaded the related information on BIPS portal.

All the broadcasters and Distributors of television channels are, therefore, advised to cornply with the respective provisions of the Register Regulation 2019 and submit all the related documents/reports as per Register Regulation 2019 on the Broadcasting & Cable Services Integrated (BIPS) portal. Further, the Members of AlDCF are advised to comply with Register Regulation 2019, keeping in view the order dated 19.05.2020 passed by Hon'ble High Court of Kerala in WP (C) No. 428/2020.

DD FREE DISH E-AUCTION

E-auction process has been opened to fill up vacant MPEG-2 slots of DD Free Dish DTH Platform on pro-rata basis for the period from 10.06.2020 to 31.03.2021. The e-auction, if needed will be held on 02.06.2020.

The categorization of TV channels in different buckets in accordance with genres / language of channel and their starting reserve price would remain same as provided in notification of even no. dated 18.03.2020.

Successful bidders shall be required to make the payments in 07 monthly lnstallments as per payment schedule prescribed under clause (5) of the policy guldelfnes for allotment of DD Free Dish slots.

Interested broadcasters may apply online at https:// fdslots.prasarbharati.orq and upload all requisite documents as prescribed in the application. The processing fee of ₹ 25,000/- will have to be paid onllne while participation fee of ₹ 1.50 Crore (Rupees one crore fifty lakhs only) is to be paid only through Demand Draft. A copy of the participation fee demand draft Is to be uploaded onllne. The original demand draft for participation fee along with printout of

ट्राई ने इंटरकनेक्शन समझौते को नियमित किया

ट्राई ने टेलीकम्युनिकेशन्स (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विस रजिस्टर ऑफ इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट और ऐसे अन्य सभी मामलों के प्रावधान **2019** का पालन करने के लिए टेलीविजन चैनलों के सभी प्रसारकों और वितरकों कों निर्देशित किया है। और इस उद्देश्य के लिए ट्राई द्वारा विकसित ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज इंटीग्रेटेड (बीआईपीएस) पोर्टल पर रजिस्टर रेगुलेशन **2019** के अनुसार सभी दस्तावेज/रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। इंटरकनेक्ट मॉड्यूल का रजिस्टर https://bips.trai.gov.in. लिंक पर उपलब्ध है।

हालांकि, यह नोट किया गया है कि कई सेवा प्रदाता रजिस्टर विनियमन **2019** के सभी प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और उन्होंने बीआईपीएस पोर्टल पर संबंधित सूचना को अपलोड नहीं किया है।

सभी प्रसारकों और टेलीविजन चैनलों के वितरकों को इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वे रजिस्टर विनिमयन **2019** के संबंधित प्रावधानों का पालन करें और ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज इंटीग्रेटेड (बीआईपीएस) पोर्टल पर रजिस्टर विनिमयन **2019** के मुताबिक संबंधित सभी दस्तावेज/रिपोर्ट को अपलोड करे। इसके अलावा एआईडीएस के सदस्यों को WP (C) No. 428/2020 में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक **19.05.2020** को पास किये गये आदेश को ध्यान में रखते हुए रजिस्टर विनियमन **2019** का पालन करने की सलाह दी जाती है।

डीडी फ्री डिश ई-नीलामी

डीडी ने **10.06.2020** से **31.03.2021** तक की अवधि के लिए प्रो-राटा आधार पर फ्री डिश डीटीएच प्लेटफार्म के खाली एमपीई जी-**2** स्लॉट को भरने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया आयोजित की है। जरूरत पड़ने पर **02.06.2020** को ई-नीलामी को आयोजित किया जायेगा।

चैनल को शैलियों/भाषा के अनुसार अलग-अलग बकेट में टीवी चैनलों का वर्गीकरण किया जायेगा और इनका आरंभिक सुरक्षित मूल्य भी दिनांक **18.03.2020** को प्रदान किये गये अधिसूचना के मुताबिक भी समान रहेगा।

डीडी फ्रीडिश स्लॉट के आवंटन के लिए नीति दिशा-निर्देश के खंड (**5**) के तहत निर्धारित भुगतान सूची के मुताबिक इसके लिए भुगतान **07** मासिक किस्तों में करने की जरूरत होगी।

ईच्छुक प्रसारक https://fdslots.prasarbharati.orq पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन में निधारित सभी दस्तावेजों को अपलोड करे। **25000**रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जबकि **1.50** करोड़ (केवल एक करोड़ **50** लाख रुपये) की भागीदारी शुल्क का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा। भागीदारी शुल्क डिमांड ड्रॉफ्ट की एक प्रति को ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए प्राप्त

acknowledgement received for submission of online application is to be submitted in sealed cover to Director (DTH) Doordarshan

Broadcasters which submitted their applications before postponing the e-auclion need not to reapply again.

NEW GUIDELINES FOR ADS

The I&B Ministry proposed new guidelines for empanelment of social media platforms with the Bureau of Outreach and Communications (BOC) for government advertisements.

BOC is the body for paid outreach by the government across print, electronic media, outdoor media and websites.

The proposed guidelines looks at the eligibility criteria for selection of social media platforms, payment procedure, terms of engagement as well as liabilities and dispute resolution in case of advertisement purchases by the BOC.

A social media platform should have a unique user base of 25 million to be eligible to apply for a contract. The numbers will be verified by the BOC based on Comscore data or Google Analytics.

Also, BOC will take a call on which platform is best suited for an outreach activity and will give preference to those platforms based in India as long as it does not impact the outcome.

The objectives of the draft guidelines are looking at improving the social media outreach of government departments and ministries as well .The draft policy guidelines once finalised will be valid for a period of five years.

पावती के प्रिंट आउट के साथ भागीदारी का मूल डिमांड ड्रॉफ्ट, निदेशक (डीटीएच) दूरदर्शन को सीलबंद कवर में प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे प्रसारक जिसने कि ई-नीलामी को स्थगित करने से पहले अपने आवेदन जमा किये थे, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

विज्ञापनों के लिए नया दिशा-निर्देश

आईएंडबी मंत्रालय ने सरकारी विज्ञापनों के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन्स (बीओसी) के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के सशक्तिकरण के लिए नये दिशानिर्देश का प्रस्ताव रखा है। बीओसी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया और वेबसाइटों पर सरकार द्वारा किये गये भुगतान पहुंच के लिए निकाय है।

प्रस्तावित दिशानिर्देश बीओसी द्वारा विज्ञापन खरीद के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के चयन के लिए पात्रता मानदंड, भुगतान प्रक्रिया, कार्य की शर्तों और देनदारियों के विवाद को देखता है।

एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म के पास एक समझौते के लिए आवेदन की योग्यता के रूप में **25** मिलियन का उपभोक्ता आधार होना चाहिए। बीओसी द्वारा कॉम्कोर डेटा या गुगल विश्लेषिकी के आधार पर संख्याओं का सत्यापन किया जायेगा।

इसके अलावा, बीओसी यह फैसला करेगा कि कौन सा प्लेटफार्म आउटरीच गतिविधियों के लिए सबसे उपयुक्त है और भारत में तब तक उन प्लेटफार्म को वरीयता देगा जब तक कि यह परिणाम को प्रभावित नहीं करता है।

प्रस्ताावित दिशा-निर्देश का उद्देश्य सरकारी विभागों व मंत्रालय के साथ-साथ सोशल मीडिया आउटरीच को बेहतर बनाने पर विचार करना। नीति दिशा-निर्देश के लागू होने के बाद यह पांच साल की अवधि के लिए वैध होगी।

TRAI EXTENDS DATE

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) had invited comments / counter-comments of stakeholders on Consultation paper on "Framework for Technical Compliance of Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management Systems (SMS) for Broadcasting & Cable services" dated 22nd April 2020. The last date for receiving of written comments and counter comments were fixed as 20th May 2020 and 3rd June 2020 respectively. Keeping in view the request of stakeholders / Industry Association for extension of time for submission of comments, it has been decided to extend the last date for submission of written comments upto 3 June 2020 and for counter-comments up to 17 th June 2020.

TELCOS DEMANDS REJECTED

TRAI has rejected the telcos' latest demand to expedite setting of a floor for tariffs by holding the open house discussions online, with chairman RS Sharma saying the watchdog needs to look after consumers who are currently in distress, a view which dealt a huge setback for operators.

TRAI chairman felt It may be a better option that any further discussion on the issue (floor tariff) is held after the lockdown is completely lifted and normalcy is restored.

Telecom carriers Bharti Airtel, Reliance Jio and Vodafone Idea wants the regulator to accelerate the process of fixing floor for service tariffs, saying in the absence of any government relief, this step was key to long-term sustainability of the sector and for carriers to absorb the adjusted gross revenue (AGR) dues.

Telcos opined that the Covid outbreak has underlined the need for a healthy telecom sector, which is capable of making investments, and to that effect, setting a floor price at the earliest was a must. They thus urged Trai to hold online open house discussions, which is the last step in the consultation process before the regulator takes a decision.

The telecom service providers want the regulator to fix a floor price for data services, while Trai, in the paper, has said not just a floor price for data but also for voice, and a price ceiling would be up for debate. ■

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक **22** अप्रैल **2020** तक प्रसारण व केबल सेवाओं के लिए ' 'फ्रेमवर्क फॉर टेक्नीकल कंप्लायंस ऑफ कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस)पर परामर्श पत्र पर हितधारकों की टिप्पणियां/जवाबी टिप्पणियां आमंत्रित की थी। लिखित टिप्पणी व जवाबी टिप्पणियों के लिए अंतिम तारीख क्रमशः **20** मई **2020** और **3** जून **2020** तय की गयी। टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए हितधारकों/उद्योग संघों की ओर से अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिखित टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर **3**जून **2020** और जवाबी टिप्पणियों के लिए तारीख को बढ़ाकर **17** जून **2020** किया गया।

टेल्कोस की मांग अस्वीकृत

ट्राई ने ओपन हाउस चर्चाओं को ऑनलाइन करके टैरिफ के लिए किसी स्तर की स्थापना में तेजी लाने के टेलीकॉम की नवीनतम मांग को खारिज कर दिया। अध्यक्ष आरएस शर्मा ने कहा कि वॉचडॉग को उन उपभोक्ताओं की देखभाल करने की जरूरत है जो वर्तमान में संकट में हैं, एक ऐसा दृश्य जो ऑपरेटरों के लिए एक बड़ा झटका था। ट्राई के अध्यक्ष ने महसूस किया कि यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि लॉकडाउन पूरी तरह से हटाये जाने और सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद इस मुद्दे (फ्लोर टैरिफ) पर कोई और चर्चा की जाए।

दूरसंचार कैरियर भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया चाहते हैं कि नियामक सेवा टैरिफ के लिए फ्लोर टैरिफ तय करने की प्रक्रिया में तेजी लाये, जो कि किसी भी सरकारी राहत के अभाव में, यह कदम इस क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और वाहक के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। टेल्कोस ने कहा कि कोविद प्रकोप ने एक स्वस्थ दूरसंचार क्षेत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जो कि निवेश करने में सक्षम है और उस प्रभाव के लिए जल्द से जल्द एक नियत कीमत निर्धारित करना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने ट्राई से इस प्रकार के ओपन हाउस चर्चा आयोजित करने का आग्रह किया, जो कि नियामक के निर्णय लेने से पहले परामर्श प्रक्रिया का अंतिम चरण होगा।

दूरसंचार सेवा प्रदाता चाहते हैं कि नियामक डेटा सेवाओं के लिए एक निर्धारित कीमत तय करे, जबकि पत्र में ट्राई ने न केवल डेटा के लिए बल्कि वॉयस के लिए भी मूल्य तय करने को कहा है और बहस के लिए प्राइस सीलिंग को रखा जायेगा। ■